20 अरब से ज्यादा वाट्सएप मैसेज भेजे हैं भारतीयों ने नव वर्ष 2020 के अवसर पर। यह वाट्सएप के दस साल के इतिहास में सबसे बड़ा आंकड़ा है। 31 दिसंबर, 2019 से एक जनवरी, 2020 तक इस बार पूरे विश्व में कुल 100 अरब वाट्सएप मैसेज का आदान-प्रदान किया गया।

न्यूज गैलरी

पंजाब में शिअद विधायक दल के नेता ढींडसा का इस्तीफा

चंडीगढ़ : पूर्व वित्तमंत्री और पंजाब विधानसभा में शिअद के विधायक दल के नेता परमिंदर सिंह ढींडसा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी प्रधान सुखबीर बादल ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। उनकी जगह साहनेवाल (लुधियाना) से विधायक शरणजीत सिंह ढिल्लों को विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया है। परमिंदर ने अपने पिता सुखदेव सिंह ढींडसा की तरह पार्टी को अलविदा नहीं कहा है। वह पार्टी में बने रहेंगे, लेकिन इससे अकाली दल के लिए मुश्किलें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। (राज्य ब्यूरो)

प्रधानमंत्री ने सावित्रीबाई फुले को दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सावित्रीबाई फुले को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उनका जन्म तीन जनवरी 1831 को हुआ था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि सावित्रीबाई फुले ने समाज की एकता, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। सामाजिक जागरूकता के लिए उनका संघर्ष हमेशा देशवासियों को प्रेरित करेगा। सावित्रीबाई फुले समाज सुधारक और शिक्षाविद् के साथ ही साथ ही एक कवियत्री भी थीं। महिला शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर साल 1848 में पुणे में महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल खोला था। (एजेंसियां)

पीएम मोदी हर हफ्ते ले रहे जीएसटी की रिपोर्ट

देहरादून : देशभर में जीएसटी संग्रह की मॉनिटरिंग खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अहम बात ये है कि यह मॉनिटरिंग हफ्तेवार की जा रही है। उत्तराखंड से सीधे पीएमओ को रिपोर्ट भेजने का असर ये है कि राज्य सरकार जीएसटी वसूली में तेजी और कर चोरी रोकने को मोर्चाबंद हो गई है। जीएसटी में रिटर्न दाखिल करने से कन्नी काटने वाले करीब 40 हजार पंजीकृत लोगों को नोटिस थमाए जाएंगे। देश में जीएसटी संग्रह में बीते कुछ समय से आए उछाल के पीछे केंद्रीय वित्त मंत्रालय व राज्य सरकार तो हैं ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खुद इस मोर्चे पर डट गए हैं। पीएमओ के निर्देश पर राज्य बीते दिसंबर माह से हर हफ्ते सीधे प्रधानमंत्री के निजी सचिव को जीएसटी पर रिपोर्ट भेज रहा है। दिसंबर के अंतिम हफ्ते में भेजी गई रिपोर्ट में जीएसटी को लेकर राज्य की सक्रियता साफ दिख रही है। साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने पर 1145 को नोटिस भेजे गए। (जासं)

अंतरिक्ष की तरह गहरे समुद्र में ताकत बढ़ाएं वैज्ञानिक

बोले मोदी ▶ पानी और खनिज जैसे विशाल समुद्री संसाधनों की जिम्मेदारी से दोहन की आवश्यकता

युवा वैज्ञानिक आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक पर करें काम

बेंगलुरु, एजेंसियां : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की सफलता अब गहरे समुद्र के क्षेत्र में भी प्रतिबिंबित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री यहां भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र को संबोधित कर रहे थे।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अंतरिक्ष की खोज में हमारी सफलता अब गहरे समुद्र के नए मोर्चे पर भी नजर आनी चाहिए। हमें पानी, ऊर्जा, भोजन और खनिजों के विशाल समुद्री संसाधनों का पता लगाने, मानचित्र बनाने और जिम्मेदारी के साथ उनका दोहन करने की आवश्यकता है।'

प्रधानमंत्री ने युवा वैज्ञानिकों से कहा कि वो देश के विकास और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाली तकनीक विकसित करने पर काम करें। उन्होंने कहा, 'देश के युवा वैज्ञानिकों के लिए मेरा आदर्श वाक्य है- इनोवेट (नया), पेटेंट (एकस्व), प्रोड्यूस (उत्पादन) और प्रॉस्पर (समृद्ध)। देश को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए इन चार स्टेप पर आगे बढ़ना होगा।' इस मौके पर उन्होंने 'आइ-एसटीईएम' नामक पोर्टल लांच किया, जो अनुसंधान के क्षेत्र में काम करेगा।

बेंगलुरु में शुक्रवार को 107वें इंडियन साइंस कांग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते नरेंद्र मोदी। प्रेट्र

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके नए दशक की शुरुआत विज्ञान के कार्यक्रम से हो रही है, पिछली बार जब वो यहां आए थे तब चंद्रयान-2 लांच हो रहा था और पूरे देश की निगाह उस पर टिकी थी। रिसर्च का इकोसिस्टम इस शहर ने विकसित किया है, जिससे जुड़ना हर युवा का सपना होता है।

नए भारत को तकनीक और तर्क दोनों चाहिए : प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत को तकनीक (टेक्नोलॉजी) और तर्क (लॉजिक) दोनों चाहिए। भारत के समाज को जोड़ने का काम विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। आज भारत में सस्ते फोन बन रहे हैं, इसकी पहुंच हर किसी के पास है और गरीब भी सरकार से जुड़ सकता है। पिछले पांच साल में ग्रामीण विकास को देश ने महसूस किया है, स्वच्छ भारत-आयुष्मान भारत इसका उदाहरण हैं।

प्लास्टिक का विकल्प खोजें वैज्ञानिक : प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का संकल्प लिया है, ताकि पशुओं और पर्यावरण को बचाया जा सके। वैज्ञानिकों को प्लास्टिक का कोई विकल्प खोजना होगा, ताकि आम इंसान को दिक्कत न होने पाए। आप जो समाधान देंगे, उसे लघु उद्योग बाजार में उतार पाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक कच्चे तेल के आयात को 10 फीसद तक कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए हमें अपने देश में बायो फ्यूल जैसे क्षेत्र में काम करना होगा। वैज्ञानिकों का यही योगदान देश की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर (350 लाख करोड़ रुपये) का बनाने में सहयोग देगा। भारत को इस तरह के वाहन बनाने होंगे, जो कि पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं।

कृषि क्षेत्र में तकनीकी क्रांति की जरूरत

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि क्षेत्र को सहायता करने वाली तकनीक में क्रांति की आवश्यकता है। क्या हम उदाहरण के लिए उंठल जलाने की समस्या को लेकर किसानों का समाधान कर सकते हैं? क्या हम अपने ईंट भट्टों को कम उत्सर्जन और अधिक ऊर्जा दक्षता के लिए फिर से डिजाइन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक के दो दिन के दौरे का शुक्रवार को आखिरी दिन था। इससे पहले उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की पांच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने तुमकुरु में श्री सिद्धगंगा मठ में भी प्रार्थना की, जहां उन्होंने राज्यों को कृषि कर्मण पुरस्कार वितरित करने के बाद एक सभा को संबोधित किया।

दिल्ली एम्स में नीट से ही होंगे दाखिले

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : अब एम्स में एमबीबीएस में दाखिले के लिए छात्रों को अलग से प्रवेश परीक्षा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस साल से संस्थान अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा। राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) के तहत ही दिल्ली सहित देश भर के सभी एम्स में भी दाखिले होंगे। इस बाबत दिल्ली एम्स ने चार दिन पहले दिशा-निर्देश जारी कर स्थिति स्पष्ट कर दी है। एम्स ने कहा है कि वह अलग से कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं करेगा।

इस तरह देश भर के मेडिकल कॉलेजों में 2020-21 के शैक्षणिक सत्र में दाखिले के लिए सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा नीट आयोजित होगी। एम्स द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि लोग संस्थान से एमबीबीएस-2020 प्रवेश परीक्षा के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि एम्स की ओर से इस संबंध में कोई सूचना जारी नहीं की गई थी। इसके मद्देनजर एम्स को दिशा-निर्देश जारी करने पड़े। पहले स्वायत्तशासी संस्थान होने के नाते एम्स खुद ही प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था। लेकिन अब एम्स भी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) दायरे में आ गया है। एनएमसी के नियमों के अनुसार देश भर में सिर्फ एक प्रवेश परीक्षा ही आयोजित होगी। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनएटी) आयोजित करेगी।

केंद्रीय विवि से जुड़ी गड़बड़ियों को लेकर सरकार का रुख हुआ सख्त

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- एचआरडी मंत्री हर महीने केंद्रीय विवि के कुलपतियों के साथ करेंगे बैठक
- इलाहाबाद विवि की गड़बड़ियों से सबक लेते हुए उठाया कदम

केंद्रीय विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी से जुड़ी शिकायतें अब लंबी नहीं खिचेंगी। इन पर तुरंत जांच के बाद सख्त कदम उठाया जाएगा। इसे लेकर मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने देश भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ हर महीने बैठक करने का फैसला लिया है। इसमें विवि के काम-काज की समीक्षा के साथ ही उनकी गड़बड़ियों को खास तौर पर देखा जाएगा।

एचआरडी मंत्रालय ने यह कदम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ गड़बड़ियों से जुड़ी शिकायतों के सामने आने के बाद उठाया है। मंत्रालय से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक निशंक और कुलपतियों की बैठक को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि यह अभी साफ नहीं हुआ है कि बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए होगी या आमने-सामने बैठ कर।

अधिकारियों का दावा है कि इस बैठक से विश्वविद्यालय के खिलाफ मिलने वाली शिकायतों में कमी आएगी। साथ ही विवि में काम-काज का एक नया माहौल बनेगा।

रमेश पोखरियाल निशंक। फाइल

मौजूदा समय में वैसे भी देश के कई विवि राजनीतिक अखाड़ा बने हुए है, जहां आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन हो रहे है। मंत्रालय इस मामले में कुलपतियों की प्रशासनिक क्षमता को भी परखना चाहता है। साथ ही वह शैक्षणिक माहौल को मजबूती देना चाहता है। केंद्रीय मंत्री के साथ कुलपतियों की बैठक में यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों को विशेष रूप से देखा जाएगा। मंत्रालय ने विवि के कुलपतियों के खिलाफ मिलने वाले ऐसी शिकायतों को लेकर काफी गंभीरता दिखाई है।

चौटाला की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे ढालिया राठी को कमान

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : हरियाणा में कई बार सत्ता में रह चुके इनेलो ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया है। इनेलो ने शुक्रवार को बड़ा फेरबदल करते हुए मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीडी ढालिया को हटाकर बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को नया प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के दौरे पर निकले इनेलो सुप्रीमो व पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला ने यह बदलाव किया है। कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक के आधार पर चौटाला ने दो बार के विधायक रहे नफे सिंह राठी को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंप दी है।

विधानसभा चुनाव से पहले इनेलो में मची उथल-पुथल के बीच अशोक अरोड़ा ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। तब चौटाला ने पूर्व आइएएस बीडी ढालिया को प्रदेशाध्यक्ष बना दिया। राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं होने के कारण ढालिया पार्टी में वह जान नहीं फूंक पाए, जिस कारण करीब छह माह बाद ही उनकी इस पद से छुट्टी कर दी गई। नफे सिंह राठी पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट नहीं मिलने से इनेलो छोड़कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे।

अब एयरबस खरीद घोटाले में चिदंबरम से पूछताछ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- मंत्रि समूह के प्रमुख के रूप में खरीद की प्रक्रिया का हिस्सा थे कांग्रेस नेता
- ईडी का दावा 43 विमानों की खरीद में हुआ था 1,000 करोड़ से अधिक का घोटाला

एयर इंडिया के लिए 43 एयरबस विमान खरीद में हुए घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से छह घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि एयर इंडिया के लिए 111 विमानों की खरीद को हरी झंडी देने वाले अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह के प्रमुख के रूप में चिदंबरम से पूछताछ की गई है। इस मामले में ईडी काफी पहले ही तत्कालीन नागरिक उड्डयन मंत्री प्रफुल पटेल से पूछताछ कर चुकी है।

ईडी के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अभी तक पूरे घोटाले में चिदंबरम की सीधी भूमिका के सुबूत नहीं मिले हैं। लेकिन अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह के प्रमुख और वित्त मंत्री के रूप में उनको विमान खरीदने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि चिदंबरम से विस्तार से पूछा गया कि आखिर एयर इंडिया के लिए 111 विमानों की खरीद की जरूरत का अंदाजा किस आधार पर लगाया गया। विमान खरीदने के दौरान सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समूह के फैसले का उल्लंघन कैसे हुआ और वित्त मंत्रालय ने एयरबस को भुगतान करते समय इस पर आपत्ति क्यों नहीं जताई?

पी चिदंबरम। फाइल

ईडी सूत्रों के अनुसार, दरअसल प्रफुल पटेल ने पूछताछ के दौरान बताया था कि विमान खरीदने का फैसला सिर्फ उनका नहीं था, बल्कि अधिकार प्राप्त मंत्रिमंडलीय समूह का था। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय से वे इस सौदे के बारे में लगातार संपर्क में थे। प्रफुल पटेल के बयान के आलोक में चिदंबरम से पूछताछ जरूरी हो गया था। दरअसल, संप्रग सरकार के दौरान शुरू में एयर इंडिया के लिए 28 विमान खरीदने का प्रस्ताव था। लेकिन बाद में सरकार ने एयर इंडिया के लिए बोइंग से 68 और एयरबस से 43 विमान खरीदने का फैसला किया।

ईडी का आरोप है कि एयरबस से विमान खरीदने में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला हुआ था। ईडी के अनुसार 2006 में सीसीएस ने एयरबस से 43 विमानों की खरीद को हरी झंडी दी। समिति ने यह भी तय कर दिया था कि किस कीमत पर ये विमान खरीदे जाएंगे। लेकिन इसके साथ यह शर्त भी जोड़ी गई थी कि एयरबस को 17.5 करोड़ डॉलर (लगभग 1,000 करोड़ रुपये) की लागत से भारत में ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहालिंग की सुविधा विकसित करनी होगी।

एयरबस से विमान तो उसी कीमत पर खरीदे गए, लेकिन ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग की सुविधा विकसित करने के लिए भारत में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की शर्त को हटा दिया। इस तरह से एयरबस को सीधे-सीधे तौर पर 1000 करोड़ रुपये का फायदा पहुंचाया गया। इसके साथ ही एक नई शर्त जोड़ दी गई। इसके अनुसार नए विमान को उड़ाने व अन्य ट्रेनिंग के लिए एयर इंडिया को अपने पायलट व स्टाफ को फ्रांस स्थित ब्लॉनैक, जर्मनी के हैम्बर्ग, अमेरिका के मियामी या फिर चीन के बीजिंग स्थित एयरबस के ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग का खर्च भी वहन करना होगा।

इस्तीफे के बाद भी बच नहीं पाएंगे हांगलू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- राष्ट्रपति ने इलाहाबाद विवि के पूर्व कुलपति के खिलाफ अनियमितताओं की जांच के भी दिए निर्देश
- यूजीसी चेयरमैन की अध्यक्षता में जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का हुआ गठन

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रतनलाल हांगलू के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न सहित सभी तरह की अनियमितताओं के लगे आरोपों की उच्चस्तरीय जांच के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति के इस निर्देश के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) ने आनन-फानन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के चेयरमैन की अगुवाई में पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित कर दी है और उसे तत्काल जांच शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

एचआरडी मंत्रालय ने बुधवार को ही इलाहाबाद विवि के कुलपति हांगलू का इस्तीफा मिलने के बाद उसे तुरंत राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया था। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक राष्ट्रपति ने शुक्रवार को उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया। हांगलू पर वित्तीय अनियमितताओं सहित प्रशासनिक और शैक्षणिक गड़बड़ियों को लेकर भी गंभीर आरोप है। हालांकि इनमें सबसे गंभीर आरोप यौन उत्पीड़न का है। जिसको लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें तलब किया था। साथ ही इसे लेकर एक अंतरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री और

रतन लाल हांगलू। फाइल

एचआरडी मंत्रालय को भी दी थी। माना जा रहा है कि इसके बाद हांगलू पर इस्तीफे को लेकर दबाव बढ़ा था। हालांकि वह इस्तीफा देकर अपने ऊपर लगे पूरे आरोपों से बरी होना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन और एचआरडी मंत्री ने जिस तरह से उन्हें लेकर सख्त रूख दिखाया है, उसे देखते हुए साफ है, कि वह इस्तीफे के बाद भी आरोपों से बच नहीं पाएंगे। वहीं जांच के लिए गठित कमेटी में यूजीसी चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह के अतिरिक्त गुजरात केंद्रीय विवि के कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दूबे और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विवि अमरकंटक(मध्य प्रदेश) के कुलपति प्रोफेसर श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी को शामिल किया गया है।

विवि के वरिष्ठ प्रोफेसर को अब मिलेगा कुलपति का जिम्मा : राष्ट्रपति से हांगलू के इस्तीफे को मंजूरी मिलने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उनकी जगह विवि के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर को कुलपति की जिम्मेदारी सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मंत्रालय ने नए कुलपति की नियुक्ति को लेकर भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू करने के संकेत दिए हैं।

आरोपों की जांच के लिए हांगलू ने बनाई थी एक सदस्यीय कमेटी : हांगलू के कच्चे-चिट्ठे राष्ट्रपति भवन से लेकर मंत्रालय तक को चौंका रहे है। एचआरडी मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक हांगलू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहे राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो अंतरिम रिपोर्ट दी है, उसके मुताबिक कुलपति रहते हुए हांगलू ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न की जांच सिर्फ एक सदस्यीय कमेटी से कराई थी। जिसने उन्हें पूरी तरह से बेदाग बताते हुए बरी कर दिया था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांचकर्ता ने शिकायतकर्ता का कोई बयान ही नहीं लिया था। इसके साथ ही विवि में यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों की जांच के लिए कोई कमेटी भी गठित नहीं थी।

'गुमनाम' चेहरे नए साल पर बने राष्ट्रपति के वीआइपी मेहमान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- कश्मीर की आरिफा व फैजल, केरल की देवकी अम्मा से लेकर सबसे छोटे हेडमास्टर के कामों को राष्ट्रपति ने सराहा

चाहे नाम मशहूर न हो मगर आपका काम बड़ा है तो फिर देर-सबेर पहचान मिल ही जाती है और जब पहचान देश की सबसे शीर्ष हस्ती की ओर से हो तो फिर बात ही अलग होती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर से लेकर कच्छ और बंगाल से लेकर केरल तक के ऐसे ही बड़े कारनामे करने वाले गुमनाम दर्जनों चेहरों को राष्ट्रपति भवन में नए साल पर खास वीआइपी मेहमान के तौर पर आमंत्रित किया। इन साधारण लोगों के बेहद खास काम को देश में सकारात्मक बदलाव के लिए अहम बताते हुए राष्ट्रपति ने इनकी दिल खोलकर प्रशंसा भी की।

कश्मीर की विलुप्त होती कला नुमधा आर्ट को जीवंत करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाली श्रीनगर की आरिफा जान हों या केरल के अलपुझा जिले में अपने खेत को ही 40 साल में जंगल में तब्दील करने वाली 86 साल की वयोवृद्ध महिला देवकी अम्मा, इनके प्रयासों से हुए बदलाव की कहानियों से सीधे रूबरू होते हुए राष्ट्रपति ने इनके योगदानों को अनुकरणीय बताया। राष्ट्रपति से हुई मुलाकात के बाद अम्मा और आरिफा दोनों ने कहा कि अचानक पिछले

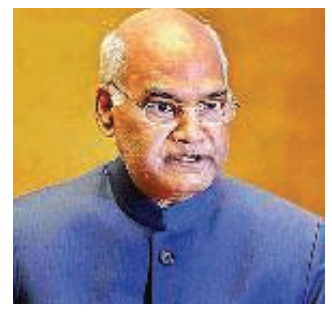
रामनाथ कोविंद। फाइल

हफ्ते जब जिला कलक्टर के यहां से संदेश आया कि उन्हें शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया गया है तो पहले उन्हें यकीन नहीं हुआ। मगर राष्ट्रपति से अपने काम की तारीफ से लगा कि हम निष्ठा से बदलाव के लिए कोई काम करें तो साधारण लोग भी सामाजिक परिवर्तन में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

किसान परिवार की देवकी अम्मा का पैर 40 साल पहले टूट गया तो खेती-बाड़ी करना मुश्किल हो गया। ऐसे में अपने पांच एकड़ खेत में इन्होंने पेड़ लगाने शुरू किए और आज केरल के अलपुझा जिले में जहां कोई सघन वन क्षेत्र नहीं है, अम्मा का बाग सबसे घना जंगल है। वहीं, आरिफा अपने सूबे की कला को नया जीवन ही नहीं दे रहीं बल्कि श्रीनगर की सैकड़ों लड़कियों को हुनर के साथ रोजगार का जरिया मुहैया करा रही हैं। जम्मू-कश्मीर के ही बांदीपुरा के किक बॉक्सिंग चैंपियन फैजल अली जो सूबे के करीब छह हजार बच्चों को अब तक निःशुल्क अलग-अलग खेलों में प्रशिक्षण दे चुके हैं, उनकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। उनके कई छात्र विश्व स्पर्धाओं में पदक जीत चुके हैं। फैजल ने बताया कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब राष्ट्रपति ने कहा कि उनके इस काम में सरकार की कैसे मदद हो इसके लिए वह सूबे के प्रशासन से कहेंगे।

नौ साल की उम्र में ही अपना स्कूल शुरू करने वाले सबसे छोटे हेडमास्टर बाबर अली की शिक्षा की लौ जलाने की कहानी भी राष्ट्रपति भवन आए इन आम मेहमानों में चर्चित रही। अब 26 साल के हो चुके बाबर ने कहा कि अपने गांव के आस पास के अपनी उम्र के स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को देखकर उन्होंने नौ साल की उम्र में पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया जो आज आनंदा शिक्षा निकेतन स्कूल में तब्दील हो चुका है। जहां 10वीं तक की शिक्षा बच्चों को मुफ्त मिलती है और बिना सरकारी मदद के लोगों की सहायता से उनका यह स्कूल चलता है। गुजरात में कच्छ के कपड़े पर ब्लॉक प्रिंटिंग को दुनियाभर में मशहूर करने वाले इस्माइल मोहम्मद खत्री और सिंचाई तकनीक के सहारे किसानों की हालत सुधारने में योगदान कर रहे बिप्लव दास, दिल्ली के फुटपाथों पर रहने वाले गरीब बच्चों के बीच काम करने वाले 'चेतना' संगठन के संजय गुप्ता सभी राष्ट्रपति द्वारा उनके कामों की सराहना से अभिभूत दिखे। फुटपाथ के बच्चों के लिए निकाले जाने वाले अपने अखबार 'बालकनामा' की प्रति राष्ट्रपति को देते हुए उन्होंने जनगणना में फुटपाथ पर जिंदगी बिताने वाले बच्चों की गणना करने का भी सुझाव दिया। वहीं गरीब खासकर ग्रामीण इलाकों के युवाओं की शिक्षा और रोजगार के लिए काम करने वाली संस्था 'फ्यूल' की मयूरी ने कहा कि राष्ट्रपति की ओर से उनके काम का संज्ञान लेना उनके लिए और बेहतर करने की प्रेरणा बनेगा। देश के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे ही बदलावों से फर्क लाने वाले साधारण लोगों को राष्ट्रपति ने खास तौर पर इसीलिए बुलाया था ताकि ऐसे अनाम चेहरों के योगदानों पर भी नोटिस लिया जा सके।

लोकपाल की परेशानी

नौ महीने बीत गए पर सरकार ने अभी तक नहीं किया अधिसूचित, सरकार और लोकपाल दोनों की जल्द ही प्रारूप अधिसूचित होने का जता रहे हैं भरोसा

कैसे हो जांच जब शिकायत का प्रारूप ही नहीं है तय

माला दीक्षित, नई दिल्ली

भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए जो सर्वोच्च संस्था लोकपाल बनाई गई है वह अभी तक भ्रष्टाचार की शिकायतों की विधिवत जांच शुरू नहीं कर पाई है क्योंकि अभी तक लोकपाल में शिकायत देने का प्रारूप ही तय नहीं है। लोकपाल को पद ग्रहण किए नौ महीने का समय बीत चुका है, लेकिन लोकपाल के समक्ष शिकायत करने का प्रारूप अधिसूचित नहीं किया गया है जिसके तहत लोकपाल भ्रष्टाचार के किसी मामले का संज्ञान लेकर विधिवत जांच शुरू कर सके। हालांकि सरकार और लोकपाल दोनों की ही तरफ से जल्द ही प्रारूप अधिसूचित होने का भरोसा जताया जा रहा है।

भ्रष्टाचार से लड़ाई की सर्वोच्च संस्था लोकपाल स्थापित करने का कानून 2013 में पास हुआ था। कानून पास होने के पांच साल बाद 2018 में लोकपाल की नियुक्ति हुई। 23 मार्च, 2018 को लोकपाल जस्टिस पीसी घोष ने पद की शपथ ली और 27 मार्च को लोकपाल के अन्य सदस्यों ने शपथ ग्रहण कर पद धारण किए। इस बीच, लोकपाल ने उसके पास आई करीब 1,200 शिकायतें निपटाई हैं, लेकिन इन शिकायतों में ज्यादातर सर्विस मैटर, जमीन विवाद या पुलिस अत्याचार आदि से जुड़े मामले थे जिनकी जांच करने का लोकपाल को क्षेत्राधिकार ही नहीं है। सूत्र बताते हैं कि कुछ शिकायतें भ्रष्टाचार से संबंधित भी आईं थीं, लेकिन उन पर विचार नहीं किया जा सका और न जांच की जा सकी क्योंकि अभी तक शिकायत दाखिल करने का प्रारूप तय नहीं है।

कानून के मुताबिक, लोकपाल में शिकायत दाखिल करने का एक तय प्रारूप होगा, जिसे केंद्र सरकार तय करेगी। सूत्र बताते हैं कि लोकपाल से प्रारूप तैयार करके सरकार को भेजा जा चुका है और सरकार को उसे मंजूरी व अंतिम रूप देकर अधिसूचित करना है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही प्रारूप अधिसूचित हो जाएगा और लोकपाल विधिवत भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू कर पाएगा। सरकार के सूत्र भी कहते हैं कि जल्द प्रारूप अधिसूचित हो जाएगा।

लोकपाल के पास अभी भ्रष्टाचार से संबंधित अगर कोई शिकायत आती है तो उसे शिकायतकर्ता को यह कहते हुए वापस कर दिया जाता है कि जब सरकार प्रारूप तय कर देगी तो उसके बाद तय प्रारूप में दोबारा शिकायत दाखिल करें और जरूरी दस्तावेज आदि दें।

बात यह है कि लोकपाल को प्रधानमंत्री, मंत्री से लेकर ए, बी, सी, डी सभी श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार है। कानून यह भी कहता है कि अगर किसी ने लोकपाल के समक्ष झूठी शिकायत की तो वह व्यक्ति दंड का भागी होगा। ऐसे में संभव है कि तय प्रारूप में शिकायतकर्ता के लिए हलफनामा आदि दाखिल करना भी जरूरी किया जाए ताकि कोई जानबूझकर किसी सरकारी कर्मचारी पर झूठे आरोप लगाने का प्रयास न करे और झूठे आरोप लगाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सूत्र बताते हैं कि लोकपाल के समक्ष जो शिकायत दाखिल की जाएगी, लोकपाल उसकी गंभीरता देखेगा और शिकायत के साथ दिए गए साक्ष्यों का आकलन करने के बाद जरूरी लगा तो मामले की जांच करेगा।

आइआरसीटीसी के किचन से ही रेलयात्रियों को मिलेगा भोजन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आइआरसीटीसी ने अपने किचन से रेल यात्रियों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इस समय आइआरसीटीसी के पास 34 किचन मौजूद हैं, जिन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही 22 नए किचन बनाए जाएंगे। यात्री सेवा समिति के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्टेशन स्थित भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के बेस किचन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि रेल मंत्री के आदेश के अनुसार रेलवे में कैटरिंग की पुरानी व्यवस्था खत्म की जाएगी। यात्रियों को सफर के दौरान पौष्टिक व ताजा खाना मिले, इसके लिए देश भर में आइआरसीटीसी बेस किचन तैयार करेगी। उन्होंने नई दिल्ली स्टेशन स्थित बेस किचन में भोजन बनाने, उसे रखने, साफ-सफाई आदि का निरीक्षण किया और अधिकारियों को भोजन की गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करने का निर्देश दिया।

कह के रहेंगे

माधव जोशी